being a communal nature and on an anti-national basis.

AN HON. MEMBER : Let him name the newspapers.

SHRI I. K. GUJRAL : Five newspapars are being denied advertisements for vulgar and sensational writings Therefore, out of the 24 newspapers which are completely barred from getting advertisements at the moment, five are such that they indulge in vulgar and in sensational writing. 19 are such that they have been barred for their communal writing, and in some cases, anti-national writing. I have already placed the list on the Table of the other House, and if the House wants, I have no objection in placing it on the Table of this House as well.

New Varieties of Foodgrains and Vegetables Developed

*633. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the names of new varieties of wheat and other food-grains and vegetables developed after research in the last three years ;

(b) the extent to which these varieties are being used by the farmers and the estimated benefit from the use of these varieties ;

(c) whether Government have chalked out any scheme to supply these varieties to small farmers at concessional rates ; and

(d) the number of new varieties expected to come out for use in the next two years ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI JAGANNATH PAHADIA) : (a) to (d). A statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The names of new varieties of wheat and other food grains developed by the Research Departments of Agriculture in States/Agricultural Universities and central Institutes and released for cultivation by the erstwhile Central Variety Reslease Committee and the Central Sub-Committee for release of seeds during the last three years, are given in the Statement. The Statement also includes the potato and other vegetables varieties/hybrids evolved at the Central Potato Research Institute and the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. The States release varieties of seeds which have application within the regions. This information is not available.

(b) The area covered during 1969-70 under the high yielding new varieties of wheat and other foodgrains is :

Wheat	6.10	million hectares
Rice	4.37	,,
Maize	0.39	,,
Jowar	0.57	,,
Bajra	1.15	,,

The extent of area covered by the new vegetable and potato strains is not available.

(c) No. But every effort is being made to make credit available to small farmers so that they are in a position to purchase seed, fertilisers etc.

(d) It is difficult to assess the exact number of new strains that are likely to come out for use in the next two years though a large amount of genetic material is in different stages of testing for their agronomic superiority.

Statement

1. List of varieties of Wheat and foodgrains released for cultivation by the Central Sub-Committee for Release of seeds and the erstwhile Central Variety Release Committee during the past three years

Wheat	Sharbati Sonora	*Rice*	Jaya
	Kalyansona		Padma
	Safed Lerma		Jagannath
	Chotti Lerma		Pankaj
	Sonalika		Sabarmati
	Hira		Jamuna
	Lal Bahadur		IR. 20
			Bala
Barley	N. P. 109		Ratna
	Jyoti		Vijaya
	R. S. 6		Krishna
			CO. 34
Maize	Ambar		Cauvery
	Vijay		Suma
	Sona		Kusuma
	Jawahar		Annapurna
	Ishan		Hamsa
	Vikram		Karuna
	Ganga-5		
		Bajra	Hybrid 2

Jowar	Swarna CSH-3	*Bajra*	Hybrid 3 Hybrid 4
Ragi	Sarda	*Pulses*	Baisaki Moong CO. 1 (beans) ADT. 1

II List of vegetable varieties released for cultivation by the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.

Tomato	SL. 120 Lal Meeruti	*Muskmebn*	Pusa-Sharbati
		Bittergourd	Pusa Domausmi
Cabbage	Pusa Drumhead	*Turnio*	Pusa Sweti Pusa Chandrima
Radish	Pusa Desi Pusa Reshmi Himani		Pusa Jyoti
Franch bean	Contender Pusa Parvati	*Palak* *Brinjal*	Pusa Jyoti Pusa Kranti Pusa Anmol (Hybrid)
Peas	Pusa Arkel Meteor	*Bottle-gourd*	Pusa Meghdut
Onion	Ratnar		Pusa Manjari
Watermelon	Sugarbady Pusa Bedana		

Varieties of Potato released by the Central Potato Research Institute, Simla

1. Kufri Sindhuri
2. Kufri Chandramukhi
3. Kufri Khasigaro
4. Kufri Naveen
5. Kufri Chamatkar
6. Kufri Neelamani
7. Kufri Sheetman
8. Kufri Alankar
9. Kufri Jeevan

श्री कंवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न के अपने उत्तर में यह कहा है। मेरे द्वारा मूल प्रश्न के पार्ट सी में सरकार से यह सवाल पूछा गया था :

"whether Government have chalked out any scheme to supply these varieties to small farmers at concessional rates ;"

The reply is :

"No. But every effort is being made to make credit available to small farmers...".

मेरा कहना यह है कि अभी तक जो वैराइटीज का लाभ हुआ है वह ज्यादातर बड़े-बड़े फारमर्स को हुआ है जो कि केवल 10 परसेंट ही है बाकी जो 90 परसेंट छोटे किसान हैं उन्होंने इस ग्रीन रैवोल्युशन की कोई झलक नहीं देखी है। उनको जो मदद सरकार से दी जाती है तो हकीकत में उस मदद का बहुत मामूली सा ही हिस्सा उनको मिल पाता है, ज्यादातर लाभ जैसा मैंने कहा जो बड़े-बड़े फारमर्स हैं उन्ही को मिल रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि छोटे फारमर्स के लिए ज्यादा लाभ हो उसके लिए सरकार कोई स्कीम क्यों नहीं बनाती ? आप की जो ईल्ड पर एकड़ है वह दुनिया में जिनकी सब से कम है उन में से यह एक है। जाहिर है कि जब तक छोटे फारमर्स के लिए कोई माकूल स्कीम नहीं बनाई जायगी तब तक आप का यह ग्रीन रैवोल्युशन सही मायनों में कोई सोशलिज्म पैदा नहीं कर सकता है। मेरा पहला सवाल यह है कि आप छोटे फारमर्स के लिए कोई स्कीम क्यों नहीं बनाते और वह छोटे किसान जोकि 200 रुपया या 300 रुपया किलो के हिसाब से नहीं खरीद सकते तो ऐसे छोटे फारमर्स को यह वैराइटीज कंसेशनल रेटस पर सप्लाई करने के वास्ते सरकार क्या कर रही है ?

दूसरे आप ने अभी तक कितना लोन नेशनलाइज्ड बैंक्स के जरिए छोटे फारमर्स को पिछले एक साल में दिया है, क्या यह ठीक है कि पहले टोटल लोन फारमर्स को 3 परसेंट था जोकि अब नेशनलाइज्ड बैंक्स होने के बाद 4 परसेंट हो गया है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि इस सदन के जरिए से और दूसरे जरिए से इस बात की सूचना

समय-समय पर दी जाती रही है कि अब जितनी भी स्कीमें बन रही हैं वह छोटे किसानों के फायदे के लिए ही हैं। माननीय सदस्य ने उन लोगों को कसेशनल रेट्स पर यह वेराइटीज सप्लाई करने के बारे में जो पूछा है कि छोटे फारमर्स के लिए क्या स्कीम है और...

श्री कंवरलाल गुप्त : छोटे फारमर्स के लिए क्या स्कीमें हैं मैं उनकी तफलीस जानना चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि केन्द्रीय रिसर्च इन्स्टीच्यूट के जरिये, राज्य सरकारों और विभिन्न एग्रीकलचरल युनिवरसिटीज के जरिए भी इस तरह की रिसर्च की जा रही है जिससे कि हम अच्छे बीज छोटे-छोटे किसानों को दे सकें। उसके जरिए से यह भी कोशिश की गई है कि न केवल अच्छे व उन्नत बीज ही दिये जा सकें बल्कि उसके साथ उनके फायदे के लिये जो दूसरे लगे हुए साधन हैं उनको भी उन्हें उपलब्ध किया जा सके। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद में जितना लोन दिया गया उस के बारे में मैंने पहले अर्ज किया कि अगर माननीय सदस्य अलग से सूचना दें तो मैं बैंकों द्वारा कितना कर्जा दिया गया उस के बारे में जानकारी दे सकता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त : उनके वास्ते क्या-क्या स्कीमें हैं यह उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा था कि कौन-कौन सी स्कीमें छोटे फारमर्स के लिए बनाई जा रही हैं? दूसरे मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि छोटे फारमर्स को बैंक नेशनलाइजेशन से पहले लोन जहां 3 परसेंट था वहां अब केवल 4 परसेंट ही हुआ है और उनको सहायता देने के लिए सरकार क्या कर रही है? यह दो सवाल पूछे थे लेकिन उन्होंने इन दोनों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया।

MR. SPEAKER : Loan for what ?

श्री कंवरलाल गुप्त : सीड्स परचेज करने के लिए, क्रेडिट और लोन के बारे में कुछ जवाब नहीं दिया है।

MR. SPEAKER : He is asking about extension service.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : The question is about seeds. He also raised the question of supply of seeds to the small farmers. This is really a very precise question. But now the hon. Member wants to go into what Government's schemes are for helping the small farmers. If he wants, I can reply to that, but this is beyond the scope of question.

MR. SPEAKER : He has asked about the scheme in (b).

SHRI ANNASAHIB SHINDE : That is, what is being done to supply seeds at concessional rates. I have said we are not supplying seeds at concessional rates to small farmers, but to enable them to purchase seeds, we are making credit available to them.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What about loan ? उसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं बतलाया है। मंत्री महोदय ने अपने मूल जवाब में यह कहा है :

> "No. But every effort is being made to make credit available to small farmers.. "

मैंने सवाल पूछा था कि पहले क्रेडिट तीन परसेंट थी जोकि अब बैंक नेशनलाइजेशन के बाद 4 परसेंट हो गयी है तो उसको और अधिक क्रेडिट मिले इसके लिए आप क्या रहे हैं.....

SHRI ANNASAHIB SHINDE : He does not read the whole—"to purchase seed, fertilisers etc".

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे काफी उन्नत बीज है जिनकी कि वैराइटीज अभी आप ने पैदा की है लेकिन उसका छोटे फारमर्स को अभी लाभ ज्यादा नहीं

हुआ है ? क्या यह सही बात है ? जाहिर है कि यह छोटे फारमर्स 200 रुपया 300 रु० किलो के हिसाब से यह सीड्स नहीं खरीद सकते और अगर यह बात सही है तो छोटे किसानों को ज्यादा लाभ हो ताकि पर एकड़ ईल्ड ज्यादा हो जाये तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

दूसरे वैजीटेबिल्स की भी बात आपने कही है । अब हालत यह है कि वैजीटेबिल्स खास कर आलू के दाम पहले से एक साल में 100 परसेंट ज्यादा हो गये हैं तो हर एक आदमी को माधूल दाम में आलू सब्जी आदि खाने को मिले इसके वास्ते सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I concede it is true that the schemes for new development in agriculture, particularly the high-yielding varieties programmes have not reached all small farmers. Therefore, Government are making every effort to see that our schemes have a broad-based. But unfortunately, the progress is not even in all parts of the country. For instance, recently the UP Agricultural Institute has carried out some studies and it found that in the western part of UP, particularly 50 per cent of the small farmers are taking advantage of new seeds, fertilisers etc. Government are trying to widen the scope. I quite appreciate the limitations ; therefore, a number of schemes have been formulated by Government to overcome them.

श्री रणधीर सिंह : व्हीट, राइस और दूसरी चीजों की नई-नई वेराइटीज मुख्तलिफ सेंटर्स में, चाहे स्टेट रिसर्च हों चाहे यूनिवर्सिटीज के रिसर्च सेंटर्स हों, चाहे सेन्ट्रल या स्टेट इंस्टिट्यूट्स हों, पैदा की जा रही हैं । उनमें ताल मेल अथवा कोआर्डिनेशन का जो काम है वह बहुत उलट-पुटल है और उससे वेराइटीज सफर करती हैं । उनमें कोई इन्टेग्रेशन या कोआर्डिनेशन नहीं है । इस सिलसिले में जो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंटर के रिसर्च सेंटर्स हैं या यूनिवर्सिटीज के रिसर्च सेंटर्स हों, जैसे पूसा है, उनमें कोआर्डिनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जायें, जिसमें वह मिलकर नई वेराइटीज पैदा कर सकें इसके लिए क्या आप के पास कोई स्कीम है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनके पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं रिसर्च के लिए क्या उन सेंटर्स के डिस्पोजल पर आप फंड्स देने के लिए तैयार हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य की इस बात का खयाल रखते हुए सरकार ने आल कोआर्डिनेटेड क्राप इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट्स भी चलाई हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स में कोआर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है । उनके जरिये से इस बात की कोशिश की जायेगी कि तरह-तरह की जो चीजें हैं, जो साधन हैं, किसान उनका उपयोग कर सके ।

श्री महाराज सिंह भारती : मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने गेहूँ के बीज में हीरा और लाल बहादुर लिखा है । इसी सत्र में मैंने मन्त्री महोदय से प्रश्न करते हुए पूछा था कि ट्रिपल जी ड्वार्फ की जो पहली वेराइटी रिलीज की गई है वह बहुत घटिया और खराब साबित हुई है, उसी तरह से कहीं हीरा तो घटिया साबित नहीं होगी । इस पर मंत्री जी ने कहा था कि लाल बहादुर तो हमने रिलीज नहीं किया था । यू० पी० पन्त नगर में जो रिलीज हुआ है वह घटिया सिद्ध नहीं हुआ है, हालांकि हीरा उससे बढ़िया है । पार्लियामेंट के इसी सत्र में एक जैसे ही प्रश्न के उत्तर में एक जगह कहा गया कि लाल बहादुर रिलीज नहीं किया गया था, वह टोटल फेल्योर रहा है, रस्ट लगा है और दूसरी जगह कहा गया कि लाल बहादुर रिलीज किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि पहला जबाब सही था या यह सवाल सही है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : This question was in the context of last year. The Rajasthan Agricultural University released this Lal Bahadur variety. At that time, it

was not actually released by the Central Varieties Release Committee. Therefore, my answer was in that context. Subsequently, the Central Varieties Release Committee, which controls this, has taken a decision to release both the strains. The experience before that was narrated in that answer. I do not think there is any inconsistency between the two replies.

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चूंकि बोने के समय छोटे किसान अच्छा बीज प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए क्या केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को यह सलाह देने पर विचार करेगी कि इसलिए उनको बीज का लोन कैश में न देकर काइन्ड में दिया जाये ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : We have already advised the State Governments accordingly.

श्री यशपाल सिंह : शंकर मक्का और शंकर बाजरा खा कर धड़ा धड़ मवेशी मर रहे हैं और इन्सान बीमार हो रहे हैं। हजारों इन्सान भी परलोक सिधार चुके हैं। पहले खड़े खेतों में आग लगाई गई थी और सरकार ने आश्वासन दिया था कि आइन्दा ऐसा नहीं होगा इस साल फिर दुनिया गंगाजी के घाट पर जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब भी वही वेराइटी बनाई जायेंगी या दूसरी वेराइटी विकसित करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आप इतना तो इन्तजार किया करें कि मैं आपका नाम लेता हूं या नहीं। कम से कम इतनी सब्र तो करें। अब चूंकि सवाल हो गया है इसलिये मन्त्री महोदय जवाब दे सकते हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सरकार के पास इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर माननीय सदस्य इस तरह का कोई केस लायेंगे हमारे ध्यान में तो हम उसकी जांच कर के कार्रवाई करेंगे।

श्री भोला नाथ मास्टर : इसमें जिन वेराइटीज को डेवेलप करने का जिक्र किया गया है वह केवल सिंचाई वाली एरिया की हैं। अगर सिंचाई में कमी रह जाती है तो जो वेराइटी डेवेलप की गई हैं वह क्राप नाकामयाब होती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी वेराइटी भी डेवेलप की गई है गेहूं कि जो बिना सिंचाई वाली एरिया में हो सके ताकि वह उन लोगों को मिल सके जिनकी भूमि में गेहूं हो सकता है लेकिन नहर या गंगा के पानी के बजाय बारिश के पानी से हो सके ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इस तरह की वेराइटीज का अन्वेषण किया गया है और उसमें कुछ को रिलीज किया गया है। कुछ अभी भी टेस्टिंग स्टेज में हैं और टेस्ट करने के बाद उन को रिलीज कर दिया जायेगा।

SHRI HEM BARUA : It is not a fact that Atomic Energy Commission Laboratory in Bombay had produced some improved variety of foodgrains like monkey nut ? May I know whether they propose to introduce the improved variety so as to improve our output of foodgrains ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : We invite the hon. Member to visit Pusa Institute where by atomic radiation processes we are trying to bring about genetical changes. I shall be glad if the hon. Member visits it.

SHRI HEM BARUA: I wanted to know something else, whether research in atomic energy laboratory in Bombay has yielded an improved variety of foodgrains or not. If so, do Government propose to utilise that to improve our foodgrains ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : We are in contact with them.

All India Co-ordinating Research Project for Coconut during IV Plan

*634. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have proposed